



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शा०)

(सं० पटना 437) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रैल 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी 2015

सं० 22/नि०सि०(मुज०)-०६-०१/२०१२/४३८—श्री सुरेन्द्र तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, सीतामढ़ी के विरुद्ध सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन में पायी गई अनियमितता की जॉच मंत्रीमंडल, (निगरानी) विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा की गयी। जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा प्रपत्र 'क' का गठन कर ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रपत्र 'क' के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री तिवारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सुरेन्द्र तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी के विरुद्ध मिट्टी कार्य की मापी Sectional Measurement के अनुसार न कर खंते की मापी लेकर करते हुए निगरानी विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 के उल्लंघन के आरोप को प्रमाणित माना गया है। अतएव श्री तिवारी के विरुद्ध मिट्टी कार्य की मापी में प्रक्रियात्मक त्रुटि का आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 1184 दिनांक 27.09.2013 द्वारा निम्न दण्ड से संसूचित किया गया।

1. 'तीन (3) वेतन वृद्धि पर असंचयात्क प्रभाव से रोक'

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री तिवारी ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक 30.10.2013 द्वारा विभाग में पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैं।

(i) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, सीतामढ़ी में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन के दौरान मेरे द्वारा मापी पुस्त में दर्ज मापी की जॉच किया जाना था, न कि मापी पुस्त में मापी अंकित किया जाना था।

(ii) जॉचित कार्यों जिनकी मूल प्रकृति मिट्टी कार्य न होकर ईंट सोलिंग कार्य है। मिट्टी कार्य में अल्प राशि प्रावधानित थी जिस हेतु Sectional Measurement किया जाना व्यावसायिक नहीं था। साथ ही Sectional Measurement नहीं किये जाने से निगरानी विभाग द्वारा निर्गत किसी दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं हुआ।

(iii) निगरानी विभाग का पत्रांक 462 दिनांक 30.03.82 अनु०-'त्र' विविध की कंडिका, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सम्पादित मिट्टी कार्यों के लिए है। जहाँ भुगतान की राशि मिट्टी कार्य की मापी पर आधारित है। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, जिनका क्रियान्वयन विभागीय रूप से होता है, में श्रमशालित का भुगतान दैनिक नामवली पर रखे गये श्रमिकों के कार्य दिवस एवं मजदूरी दर पर आधारित है। जिसके प्रत्येक कार्य हेतु दैनिक नामवली संधारित किया

जाता है जिसकी सम्पुष्टि मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 733 दिनांक 09.03.94 से होती है। कार्य नियोजित मजदूरों के पूर्ण दैनिक पारिश्रमिक भुगतान हेतु उनके लिए निर्धारित दैनिक कार्य की मात्र के अनुरूप कार्य करने की अनिवार्यता है। जिसका आकलन खते की मापी से ही संभव है। न कि Sectional Measurement से। ऐसी स्थिति में निगरानी विभाग का पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(iv) ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं0 7827 दिनांक 01.08.98 की कंडिका (v) में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि जल संसाधन विभाग के 63 (तिरसठ) प्रमंडल, जिनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गयी है, का कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 प्रमंडलों के अनुरूप ही होगा।

(v) इसी मामले में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री रघुवर तिवारी जिनका कैडर झारखंड राज्य को सौंपा गया को आरोप मुक्त किया गया है।

श्री तिवारी द्वारा समर्पित पूनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न बाते पायी गयी।

ग्रामीण विकास विभाग, पटना की अधिसूचना संख्या 7827 दिनांक 01.08.1998 के कंडिका (5) में अंकित है कि इन प्रमंडलों का कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 प्रमंडलों के अनुरूप ही होगा। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 853 दिनांक 15.02.2008 में यह उल्लेखित है कि मिट्टी कटाई की गणना साक्ष्य स्तम्भ के आधार पर की जायेगी और यह वैसी योजनाओं पर लागू होगी जिसमें मिट्टी की कुल मात्रा 1.8 लाख घन फीट से अधिक न हो। चूंकि श्री तिवारी को दण्ड इसी आधार पर दिया गया था कि उनके द्वारा Sectional Measurement (साक्ष्य स्तम्भ) के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की गई है। परन्तु श्री तिवारी द्वारा उद्घृत ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक 853 दिनांक 15.02.2008 का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि Sectional Measurement (साक्ष्य स्तम्भ) के स्थान पर मिट्टी कार्य की गणना का नया प्रावधान दिनांक 15.02.2008 से लागू किया गया है। जबकि श्री तिवारी द्वारा कराई गई योजनाएँ वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–2004 के बीच की हैं।

अतः पूनर्विलोक अर्जी में दिये गये आधार मान्य नहीं है। जिस कारण श्री तिवारी के पुनर्विलोकन अर्जी को निरस्त करते हुए पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या 1184 दिनांक 27.09.13 द्वारा निर्गत दण्डादेश को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री सुरेन्द्र तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, सम्प्रति अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर, अवर प्रमंडल सं0–3, झांझारपुर (मध्यबनी) को संसूचित किया गया है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 437-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>